Publication Date 01.02.2025
Postal Registration No. G/CHD/0096/2024-26
Registrar of Newspapers of India
Regd. No. 46809/70 I Total Pages 32
Posted at MBU Chandigarh 1st of Every Month

हरियाणा सहकारी प्रकाश

Haryana Sahkari Parkash

वर्ष : 56 | अंक 02 | 1 फरवरी, 2025 | वार्षिक मूल्य : 500/- | प्रति कापी : 50/-

विकास का मार्ग केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है।

हरियाणा सहकारी प्रकाश के सुधी पाठकों को बसंत पंचमी व महा शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

HARCOFED
Bays No. 49-52, Sector - 2, Panchkula
https://www.harcofed.org.in
harcofed@ymail.com

सम्पादकीय

आर्थिक विकास के लिये मिल-जुल कर काम करने का नाम है सहकारिता

सहकारिता मानव जीवन में प्रारम्भ से ही रची–बसी एक प्राकृतिक देन है। मनुष्य किसी हालात में किसी भी स्थान पर रहे यह एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करता है व सहयोग देता है। परिभाषा के रूप में सहकारिता को जानना हो तो प्रायः मिल–जुल कर काम करने को सहकारिता कहा जाता है। सहकारी आन्दोलन एक ऐसा तत्र है जिसमें व्यक्ति अपने स्रोतों को समूह के लिये प्रयोग करता है तथा स्वयं के साथ–साथ दूसरों की सहायता भी करता है। एक Team work होने के कारण Together Every one Achieves More सहकारिता का मुख्य अंश बन गया है और इस आशय को प्राप्त करने की सहकारी आन्दोलन में अपार ही नहीं अपितु असीम सम्भावनाएं भी विद्यमान हैं।

मनुष्यों में स्वःभाविक तौर पर असमानताए पाई जाती है। एक व्यक्ति किसी कार्य को खूब अच्छे ढंग से सम्पन्न कर पाने में सक्षम होता है तो दूसरा उसी कार्य को करने में असमर्थ। यह भी सम्भव है कि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य कार्य को करने में निपुण हो। सहकारिता के आधार पर कार्य करते हुये सभी व्यक्ति अपनी योग्यता एवं स्रोत को इकट्ठे तौर पर प्रयोग कर वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

आज के युग में श्रम का विभाजन हो रहा है। श्रमिक या कार्यकर्ता किसी विशेष कार्य को करने में विशेषज्ञता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में भी सहकारिताओं के समक्ष उपयुक्त सम्भावनाएं हैं कि वे श्रमिकों को और कार्यकर्ताओं के कौशल को सामूहिक रूप में प्रयोग करें। सहकारी तन्त्र से सदस्य, प्रबन्धक कमेटी तथा सस्था के मुख्य कार्यकारी में समन्वय आवश्यक है। तीनों के घनिष्ठ तालमेल से ही समितियां सफलता की ओर बढ़ सकती हैं। समय है आज प्रबन्धकीय तंत्र में दक्षता लाकर समर्पित भाव से काम करते हुये सहकारी संस्थाओं में व्यवसायिक ढंग से कार्य करने का। यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसका स्वामित्व एवं नियन्त्रण आम जनता के हाथ में है। यहां हर कदम यह सुनिश्चित करने के लिये उठाया जाये कि बाजार के कुप्रभाव एवं विघटनकारी शक्तियां इस के स्वरूप को न बिगाड़ पायें और आर्थिक उदारता की ओर बढ़ता यह आन्दोलन निर्बाध रुप से कार्य करता रहे। यही आन्दोलन की खुबी तथा यही आन्दोलन की शान है।

राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आन्दोलन के इतिहास पर दृष्टि डालने से इस आन्दोलन का लम्बा एवं गौरवमयी इतिहास जान पड़ता है। सी वर्ष से भी अधिक के कार्य काल में आन्दोलन का कई गुणा प्रसार हुआ है तथा अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने में सहकारी आन्दोलन ने मुख्य भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के स्तम्भ के रूप में सहकारी आन्दोलन ने अपनी विशेष पहचान बनाई है तथा यह चीनी, डेयरी श्रम, ऋण, आवास व उर्वरक जैसे क्षेत्रों में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सब कुछ आन्दोलन के मूल्यों एवं सिद्धान्तों में विश्वास और निष्ठा के कारण सम्भव हो पाया है। वर्तमान संदर्भ में विश्वास और मूल्यों पर आधारित सहकारिता आन्दोलन पूंजीवाद के उस तंत्र से कहीं अधिक प्रासंगिक है जहां पूंजीवाद संगठन का एक जन–आन्दोलन होने के कारण विस्तृत आधार बना चुका है। कृषि व कृषि कार्यों के लिये ऋण प्रदान करने हेतु अपनी विशेष पहचान बना चुके इस आन्दोलन का आधार विशेष रूप से गांवों में तथा कृषि से जुड़े परिवारों से के साथ सम्बन्धित है।

यह सब होते हुये भी अति आवश्यक है ऐस सहकारी गतिविधियों का परिचालन ऐसे ढंग से किया जाये कि वह प्रमाणिकता की कसौटी पर खरा उतरे तथा जनता के विश्वास को भी बनाये रखा जा सके। यह भी आवश्यक है कि समय के साथ–साथ आन्दोलन के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों एवं व्यवहारिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निबटते हुये आत्मविश्वास के साथ कार्य किया जाये। यह तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता कि सहकारी आन्दोलन सबल है, सक्षम है, पर्याप्त है तथा विकास की हर डगर पर खरा उतर सकता है केवल इसे आत्मविश्वास और समर्पित भाव से मार्गदर्शन प्रदान की आवश्यकता है।

हरियाणा सहकारी प्रकाश

संरक्षक
राजेश जोगपाल, भा.प्र.से.
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा

मुख्य सम्पादक
नरेश गोयल
प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड

सम्पादक
सौरव शर्मा

सुविचार

"अधिकार मनुष्य को तब तक अन्धा बनाये रखेंगे, जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे।"

–सरदार वल्लभ भाई पटेल

'हरियाणा सहकारी प्रकाश' में प्रकाशित लेखकों के विचारों के साथ हरकोफैड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेखकों के अपने विचार हैं।

हरियाणा सहकारी प्रकाश की विज्ञापन दरें :–

क्र.सं.	विवरण प्रति प्रकाशन	रुपये
1.	पूरा पृष्ठ टाईटल रंगीन	30000/-
2.	पूरा पृष्ठ रंगीन	20000/-
3.	पूरा पृष्ठ श्याम–श्वेत	12000/-
4.	आधा पृष्ठ श्याम–श्वेत	6000/-

इस अंक में पढ़िए

सम्पादकीय 2

श्री अमित शाह ने NCOL की समीक्षा बैठक में सहकारी ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जोर 5-6

38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का होगा भव्य आयोजन 6

मुख्यमंत्री रेवाड़ी में 76वें गणतंत्र दिवस पर फहराया ध्वज, शहीदों को नमन 7-11

पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत 12-14

हरकोफैड चेयरमैन वेद प्रकाश फूल्लां ने कालका में किया ध्वजारोहण 15-16

दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला : मंत्रिमंडल ने दिव्यांग पैंशन नियमों में दी संशोधन को मंजूरी 17

अब शुगर फ्री प्रॉडक्ट भी बनाएगा वीटा 18

सहकारिता मंत्रालय 2024: विकास, नवाचार और समृद्धि की ओर बढ़ते कदम खुशहाल प्रदेश, समृद्ध गांव सहकारिता द्वारा 19-21

खुशहाल प्रदेश, समृद्ध गांव सहकारिता द्वारा 21

युवा उत्थान में सहकारिताओं की भूमिका 22

बच्चे देश का भविष्य 23-24

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति 25-28

कहानी धरती माँ है रे.. 28-29

विज्ञापन 30

E-MAIL
harcofed@ymail.com
harcopress@gmail.com

Website
https://www.harcofed.org.in

हरकोफैड के प्रबन्ध निदेशक नियुक्त हुए श्री नरेश गोयल

पंचकूला दिनांक 30 दिसबंर, 2024 को श्री नरेश गोयल, सयुंक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ हरियाणा को हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री नरेश गोयल हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार भी संभाले हुए हैं।

इन्होने जनवरी, 2004 में हरियाणा सिविल सेवा के माध्यम से सहकारी विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पदार्पण किया था। विभिन्न स्थानों पर सहकारिता विभाग की सेवा करते हुए इन्होने कृषक व कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान में अपना विशेष योगदान दिया। इनको केन्द्रीय सहकारी बैंक कैथल, महेन्द्रग्रढ़, जींद व हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

सन् 2017 में संयुक्त रजिस्ट्रार पदोन्नत हुए और सहकारिता विभाग मुख्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। सन् 2018 में श्री नरेश गोयल हरकोफैड में प्रबंध निदेशक के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

आप जैसे अनुभवी एवं प्रतिभावान अधिकारी के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने से आशातीत हैं कि हरकोफैड द्वारा सहकारिता विभाग के प्रचार–प्रसार के कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को ओर तेज गति प्रदान होगी और सहकार से समृद्धि का संदेश जन–जन तक पहुंचेगा।

श्री अमित शाह ने NCOL की समीक्षा बैठक में सहकारी ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जोर

देश में सभी PACS को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़ ऑर्गेनिक उत्पादों का बढ़ावा देने का अभियान चलाया जाये

ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता का पर ध्यान देना NCOL की प्राथमिकता हो

ऑर्गेनिक उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग और उचित मूल्य मिलने से किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित होंगे

NCOL द्वारा उत्तराखंड के किसानों से खरीदे गए धान से किसानों 10% से 15% तक का अधिक लाभ हुआ

सभी PACS ऑर्गेनिक उत्पादों और बीजों की बिक्री के केन्द्र बनें

नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में नेशनल कॉपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव श्री पंकज बंसल, नेशनल कोपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मिनेश शाह और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के.वी. सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

बैठक के दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि देश में सभी PACS को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाना चाहिए। उन्होने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि NCOL को अपने "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत किसानों से ग्राहकों तक प्रामाणिक जैविक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को शुद्ध प्रमाणिक जैविक उत्पाद बाजार में सुलभ हो सकें इसमे NCOL को प्रत्येक 'भारत ऑर्गेनिक्स' उत्पाद के बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अमूल की डेयरियां और एनडीडीबी की सस्थाओं से जुड़े किसानों को भी आर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों के बदले उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि वे ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रेरित हो सकें। श्री अमित शाह ने NCOL और सहकारिता मंत्रालय को कहा

कि अमूल के साथ Bharat Or–ganics पर एक बैठक करके ऑर्गेनिक आटे, और ऑर्गेनिक अरहर दाल के दामों को इस प्रकार से निश्चित करना चाहिए जिससे किसानों को फायदा पहुंचे और वे ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा प्रेरित हों। श्री शाह ने कहा कि एक बार अगर किसान को ज्यादा दाम मिलने की शुरुआत होगी तो निश्चित ही किसान धीरे–धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगर मार्केटिंग अच्छी होगी, तो जिस प्रकार से ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता है, उससे निश्चित रूप से पूरे देश में इन उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने आगामी पर्व–त्योहारों में ऑर्गेनिक उत्पादो को ओर बढ़ावा देने की अपील की।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी PACS कृषि उत्पाद के स्रोत, ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के केन्द्र, और बीजों की बिक्री के केन्द्र बनें ताकि छब्व्स्ए छब्म्स् और ठठैस् जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन 2 लाख सहकारी समितियों में कम से कम एक ऐसे युवा किसान को जोड़ना चाहिए जो आगे चलकर स्थानीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में प्रेरक का काम कर सके। श्री शाह ने PACS के सदस्यों के साथ–साथ किसानों के समुचित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड को सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नये PACS ऐसी कार्यप्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिससे प्रत्येक किसान को उसके क्षमता के अनुरूप ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का होगा भव्य आयोजन

चंडीगढ़। रंग, शिल्प, संगीत, लय, कला और संस्कृति के एक आनंदमय उत्सव स्वरूप 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में आने वाले लाखों आगंतुकों के स्वागत की तैयारियां दिन पर दिन तेजी से पूरी की जा रही हैं। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में पहली बार एक साथ 15 राज्यों के पारंपरिक व लजीज व्यंजन का आनंद आगंतुक उठा पाएंगे। यही नहीं, खानपान क्षेत्र के नामी और वैश्विक ब्रांड्स भी अलग–अलग स्थान पर अपने स्टॉल्स पर आमजन को लुभाएंगे। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का 38वां संस्करण कई मायनों में खास होने जा रहा है। सूरजकुंड में 17 दिन तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार क्षेत्रीय खानपान की जितनी विविधता नजर आएगी, उतनी पहले कभी देखने को नहीं मिली।

भारतीय ही नहीं, विदेशी पर्यटक इस बार मेला मैदान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत की पांरपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि इस बार थीम स्टेट मध्य प्रदेश, उडीसा, मेजबान राज्य हरियाणा के साथ–साथ

राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना राज्य की पारंपरिक खानपान का स्वाद आगंतुक चख सकेंगे। यही नहीं, इन राज्यों के स्टॉल्स पर चुनिंदा व्यंजन नहीं रहेंगे, बल्कि हर राज्य के 10 से 15 पारंपरिक पकवान उपलब्ध होंगे, ताकि आमजन को भरपूर वेरायटी मिले। मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के स्टॉल्स भी अलग– अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। आमजन को खाने की विविधता भरपूर मिले, इसके लिए सभी छह जोन में वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि पहली बार खानपान क्षेत्र के वैश्विक बांड्स भी इस बार मेले में नजर आएंगे।

मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में 76वें गणतंत्र दिवस पर फहराया ध्वज, शहीदों को किया नमन

भविष्य में हरियाणा देश के समक्ष विकास, उन्नति और उत्कृष्टता का बनेगा उदाहरण – नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने लोगों से देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने का किया आह्वान

शहीदों, सैनिकों व अग्निवीरों का हरियाणा सरकार ने किया सम्मान

पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था बनाने के लिए ई-गवर्नेंस का मॉडल किया तैयार – मुख्यमंत्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ–साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में हरियाणा देश के समक्ष विकास, उन्नति और उत्कृष्टता का उदाहरण बनेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को

अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को जिला रेवाड़ी में आयोजित समारोह में ध्वज फहराया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड तथा स्काउट्स इत्यादि की टुकड़ियों की परेड का भी निरीक्षण किया और सलामी ली।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह उनका पहला अवसर है और उनके लिए यह परम सौभाग्य है कि यह अवसर उन्हें वीर भूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खानपान और संस्कृति को समेटे हुए है। यह विविधता में एकता का उदाहरण है। इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 'हमारा संविधान–हमारा स्वाभिमान' अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

शहीदों, सैनिकों व अग्निवीरों का हरियाणा सरकार ने किया सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणावासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन् 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों

को प्रेरित करने के लिए अम्बाला छावनी में 538 करोड़ रुपये की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि दोगुनी करके 1 करोड़ रुपये की गई है। सरकार ने वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा, अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दी जा रही है। हाल ही में, यह पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये की है।

पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था बनाने के लिए ई-गवर्नेंस का मॉडल किया तैयार

सुशासन को जनसेवा का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई–भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई–गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान–पत्र से जोड़ा गया है। बिना खर्ची–पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी–लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देशभर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक–हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किये हैं और आज हरियाणा विकास के मामलों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। हमारी डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को तीन गुणा रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे।

हर दिन ले रहे जनकल्याणकारी निर्णय

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद गरीब लोगों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। आयुष्मान भारत–चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केन्द्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में बांटकर अब तक समाज की मुख्यधारा में आने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। गरीब परिवारों के लिए हैप्पी योजना के माध्यम से रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है।

4,533 पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के गांवों में 100–100 गज और महाग्रामों में 50–50 गज के प्लाट देने की शुरुआत की गई है। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार 573 मकान बनाये गये हैं। लगभग 14 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30–30 गज के प्लाट दिए हैं। उन्होंने कहा कि पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 12 हजार 285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

अन्नदाता के हितों का रख रहे विशेष ख्याल

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज हरियाणा किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करता है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये भी डाले जा चुके हैं। खरीफ सीजन में बारिश देर से होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस दिया है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही 133 करोड़ रुपये की पिछली बकाया राशि भी माफ कर दी है। इसके अलावा, खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई

टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200 प्रतिशत व लाइन के नीचे की भूमि के लिए मार्केट रेट के 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत करने के लिए तीन और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू–मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब हमने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है।

2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। पारंपरिक काम करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पी.एम. विश्वकर्मा योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 1 लाख 71 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में ठेकेदारों के हाथों युवाओं का शोषण होता था। हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है।

राष्ट्रपति ने प्रदेश के 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का नाम दुनियाभर में चमकाया है। ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा 1 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। सरकार की हर गांव में जिम खोलने योजना के तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे सार्थक कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ–बेटी पढाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को सम्बन्धित गांव का ब्रांड अम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक पौने 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 'ड्रोन दीदी योजना' के प्रथम चरण में 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपये तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 79 कॉलेज खोले हैं। इनमें 30 लड़कियों के हैं। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक–तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। श्अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है।

गत सवा 10 वर्षो में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार एमएसएमई उद्योग लगे, इनमें 39 लाख लोगों को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने इंज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको–सिस्टम तैयार किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश–विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत सवा 10 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों व कर दाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सभी 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में जी.एस.टी. सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। राज्य में खरीफ वर्ष 2024–25 के दौरान प्रदेश में कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए सभी राईस मिलर्स को 31 अगस्त, 2024 तक 62.58 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि स्वरूप बोनस दिया गया है।

ग्राम पंचायतों को दिए अधिक अधिकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपये की गई है। प्रदेश के 5868 गांवों में श्म्हारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का मासिक न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' कर दिया है। आज हर ब्लॉक के 10 सबसे अधिक आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। अब तक 283 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है व 179 गांवों में प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि पीएम ई–बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की गई हैं। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने गत 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। प्रदेश में हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं, जिनमें से 8 का कार्य पूरा हो चुका है। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों तथा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी रही प्रथम राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से संबंधित झांकियों को भी प्रदर्शित किया गया। झांकियों में महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी प्रथम, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य विभाग) की झांकी द्वितीय व साइबर अपराध (पुलिस विभाग) की झांकी तृतीय स्थान पर रही। समारोह में जिला के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विविधता में एकता की झलक देते हुए बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।

मार्च पास्ट में दुर्गा शक्ति की टुकड़ी रही पहले पायदान पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड कमांडर वाईवीआर शशि शेखर आईपीएस एएसपी रोहतक की अगुवाई में हरियाणा पुलिस पीएसआई करण सिंह, दुर्गा शक्ति, रेवाड़ी पीएसआई संगीता देवी, उत्तराखंड पुलिस एसआई युद्धवीर सिंह, महिला पुलिस एसआई सर्वेष्ठा, दुर्गा शक्ति, रोहतक एएसआई सोनू, होमगार्डस प्लाटून कमांडर सुधीर कुमार, हरियाणा पुलिस अकादमी एएसआई सुनील कुमार सैनिक स्कूल गर्ल्स कैडेट पारुल, एनसीसी सीनियर गर्ल्स कैडेट खुशबू, एनसीसी सीनियर बॉयज कैडेट विपिन यादव, स्काउट्स एंड गाइड स्काउट अंकित खत्री, गर्ल्स गाइड गाइड प्रिया व प्रजातंत्र के प्रहरी लक्ष्मी के नेतृत्व में मार्चपास्ट की टुकडियों ने कदमताल करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। मार्च पास्ट में दुर्गा शक्ति रेवाड़ी की टुकड़ी ने पहला, एन.सी.सी सीनियर बॉयज की टुकड़ी ने दूसरा तथा उत्तराखंड पुलिस की टुकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया।

समारोह में ये रहे मौजूद राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, एडीजीपी सी.आई.डी सौरभ सिंह, डीसी अभिषेक मीणा, आईजी साउथ रेंज अशोक कुमार, डीआईजी सीआईडी पंकज नैन (आईपीएस), जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा, एसपी मयंक गुप्ता, एसपी सिक्योरिटी अजीत सिंह शेखावत, एसपी सिक्योरिटी–2 राजकुमार वालिया, एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह, सीटीएम प्रीति रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली, पी.पी.पी स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला, नपा चेयरपर्सन पूनम यादव, हिमांशु पालीवाल, डॉ. अरविंद यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता वीर कुमार यादव, मास्टर हुकम चंद सहित गणमान्य व्यक्ति व अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत

: डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

76 वें गणतंत्र दिवस समारोह में देशभक्ति की भावना से सराबोर कार्यक्रम में दिखी देश की उन्नति व प्रगति की झलक

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा बतौर अतिथि हुए शामिल, परेड की सलामी लेते हुए फहराया राष्ट्रीय ध्वज

गणतंत्र दिवस पर झज्जर में झांकियों का जलवा, देश भक्ति और विकास का अनोखा संगम

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने जिला सैनिक बोर्ड संग्रहालय के लिए पांच लाख और भागीदार छात्रों को बतौर पारितोषिक दो लाख रुपये देने की घोषणा की

जिला झज्जर में देश का 76वां गणतंत्र दिवस रोडवेज वर्कशॉप प्रांगण में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। प्रदेश के सहकारिता, कारागार, चुनाव, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराया और परेड़ की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करती झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि ने समारोह में मौजूद युद्ध वीरांगनाओं, शौर्य पदक विजेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और आपातकाल के पीड़ितों को सम्मानित किया । विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों, छात्रों, समाज सेवकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने अपने स्वैच्छिक कोष से जिला सैनिक बोर्ड संग्रहालय के लिए पांच लाख और गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदार छात्रों को बतौर पारितोषिक दो लाख रूपये देने की घोषणा की ।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कि 75 वर्ष पहले सन् 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था यह संविधान ही है जिसने हमें अनेकों अधिकार दिए हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार हमारा संविधान हमारा –स्वाभिमान कार्यक्रम चलाकर पूरे देश में संविधान के प्रति अलख जगा रहे हैं। यह आजादी हमें अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदानों से मिली है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस वर्ष का थीम है स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास ।

यह थीम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। किसी भी राष्ट्र को स्वर्णिम बनाने के लिए उसकी विरासत को सहेज कर रखना अति आवश्यक है विरासत को कायम रखते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पीएम मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि झज्जर महान वीरों की भूमि है। यहां महान स्वतंत्रता सेनानी पं श्रीराम शर्मा, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, सेना अध्यक्ष रहे दलबीर सुहाग ने जन्म लिया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि धार्मिक तौर पर भी यहां का महत्व कुछ काम नहीं यहां मां भीमेश्वरी देवी मंदिर, गरीबदास पीठ, ठाकुरद्वारा, सिद्ध बाबा प्रसाद गिरि जी महाराज, काशी गिरी मंदिर व हनुमान मंदिर स्थित हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने वादे के अनुसार शपथ लेते ही पहले कलम से 25000 युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सेना में हर 10 में से एक सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा प्रदेश के सभी नौजवान भारतीय सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अब सेना के साथ–साथ सरकार ने अग्नि वीर नीति भी लागू कर दी है जिससे हरियाणा अग्नि वीरों को सुरक्षा कवच प्रदान करके किया जाएगा। स्वच्छ व स्वस्थ हरियाणा के लिए प्रदेश सरकार ने 250 गांवों में इंडोर जिम की सौगात दी, ताकि युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो तथा 1000 ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, ताकि युवाओं को अध्ययन के लिए बेहतर माहौल मिले।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि खेल जगत में हरियाणा एक बहुत बड़ा नाम है हमारे खिलाड़ी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाडियों को नगद पुरस्कार देने के साथ–साथ सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कुल 6 पदक आए थे जिसमें से पांच का योगदान हरियाणा के खिलाडियों का है। खास बात ये है कि छह पदकों में से तीन पदक झज्जर जिले के खिलाड़ियों के नाम हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि कि सरकार ने महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया। इसके अलावा अटल किसान मजदूर कैंटीन, वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। सहकारिता समितियों के गठन में भी महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जाते हैं । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लखपति दीदी और ड्रॉन दीदी जैसी मुहिम की शुरुआत की गई, जिसका सीधा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर घर, हर गृहिणी योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले लगभग 51.72 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हरियाणा में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अब महिला सरपंचों को संबंधित गांव का ब्रांड एंबेसडर बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दस हजार और नए आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व ही महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के मकसद से प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत में बीमा सखी योजना शुरू की। इसके अलावा 100 नए महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों को डिजिटल बनाने के लिए 10 फाइबर टू दा होम कनेक्शन देने की घोषणा की है। जिसके द्वारा 2 साल तक निशुल्क हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं में गोवंश के चारे के लिए 216 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि झज्जर जिले के विकास को लेकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बादली गांव को खंड तहसील और उपमंडल का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहादुरगढ़ मुंढका मेट्रो रेल लाइन का निर्माण 1900 करोड़ रुपए की लागत से किया गया तथा बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट के विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जल्द ही बाढसा, बादली और फिर झज्जर तक भी मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा। सडक मार्गों के विकास की बात करें तो बेरी के रोहतक बावल सडक को 650 करोड रुपए की लागत से चारमार्गी बनाया गया। जिला के गांव जैसोरखेड़ी से दिल्ली– अमृतसर –कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा की सीमा में कार्य पूरा हो गया है और इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जेएलएन फीडर सालावास के नवीनीकरण पर 143 करोड़ रुपए खर्च किए गए। के.एम.पी. केजीपी. जैसी आधुनिक परियोजनाओं के बाद अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय काले खा से करनाल तक आर.आर.टी.एस. रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है।

गणतंत्र दिवस समारोह में जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी, महिला निगम की पूर्व चेयरमैन सुनीता चौहान महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष सोमवती जाखड़, मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, विधान सभा प्रभारी दिनेश शेखावत, प्रमोद बंसल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे ।

जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस कमिश्नर बी. सतीश बालन, डीसी प्रदीप दहिया, डीसीपी मुख्यालय दीपक सहारण, एडीसी सलोनी शर्मा, डीसीपी झज्जर लोगेश कुमार पी., डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा, एएसपी शुभम, एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, सीईओ जिला परिषद राजेश कुमार, सीटीएम परवेश कादयान सहित अन्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारी मौजूद रहे।

हरकोफैड चेयरमैन वेद प्रकाश फूल्लां ने कालका में किया ध्वजारोहण

हरकोफैड चेयरमैन श्री वेदप्रकाश फूल्लां ने कालका, पंचकूला के श्रीमती अरूणा आसफ अली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका के खेल मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण किया और परेड़ का निरीक्षण किया और परेड़ को सलामी दी।

उन्होने मंच से अपने सम्बोधन में कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज, मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि सभा के तमाम सदस्यों की बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है।

श्री वेद प्रकाश फुला ने कहा कि 'सुशासन से सेवा' के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ–सबका विकास' और 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' के मूलमंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कम्प्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई–गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार, परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोडा गया है।

उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक–तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' व वीटा बिक्री

केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन–बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कालेज स्थापित किया है। पंचायतों, नगर निगम और पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बीसी–ए वर्ग में 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, अब बीसी–बी वर्ग के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में बीसी–बी वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।

उन्होंने युवा साथियों को खुशी बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25 हजार से अधिक अभ्यार्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया अपना वायदा पूरा किया। इस मौके पर एसडीएम कालका राजेश पुनिया, नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लाम्बा, नगर परिषद ईओ जरनैल सिंह, तहसीलदार विवेक कुमार, खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी विनय प्रताप, श्री काली माता मंदिर कालका सचिव पृथ्वी राज सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस पर इनको किया सम्मानित

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा वार विडो और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल भेंट की। विभिन्न प्रस्तुतियों में हिस्सा लेने वाले सभी स्कूलों की टीमों को सम्मानित किया गया। अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डा. रिशू मित्तल, छात्र निशांत, जसकरण, सवलीन कौर, सूर्या सेठ, सुजैन जैकी, खुशी और हितेश, अध्यापक आशा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता में भूषण दीक्षित, चरणप्रीत सिंह, हितेश पाहवा, शेरचंद चावला, कर्ण जोशी, कर्मचारियों में दिग्विजय सिंह, मदन सिंह, कविता, अरविन्द्र कौर, एसआई नरेन्द्र कुमार, एएसआई कविता, एएसआई कप्तान सिंह, एचसी गुरगेज सिंह, धर्म सिंह, कुलविन्द्र सिंह, विक्रम, संजय कुमार, रोहताश, रत्तन लाल, नीतिश कुमार, कश्मीरा सिंह, लेखराज, नसीब सिंह, अनुराधा, अंकित कुमार, ओमबीर, नरेन्द्र कुमार, सपना, सिमरन, राजेश कुमार, विजय, रवि कुमार, गुरुदयाल, विजय कुमार को सम्मानित किया गया।

मार्च पास्ट में 15 टुकड़ियां रही शामिल

गणतंत्र दिवस के मार्च पास्ट में 15 टुकड़ियां शामिल रही। इनमें परेड सीडीवी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा गृहरक्षी, राजकीय कॉलेज एनसीसी, राजकीय कॉलेज एनसीसी लड़कियां, राजकीय स्कूल कालका एनसीसी, राजकीय स्कूल पिंजोर, सोफिया कॉनवेंट स्कूल, आर्य गर्ल्स स्कूल कालका, सिख गर्ल्स हाई स्कूल, संत विवेकानन्द मीलिनियम एनएसएस, डीएवी सुरजपुर, अकाल जोत, यूनिसन इंटरनेशन स्कूल पिंजोर की टुकड़ियां शामिल रही।कार्यक्रम में आर्य गर्ल्स स्कूल कालका, सोफिया स्कूल, सिख स्कूल, राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने पीटी शो प्रस्तुत किया। दर्शन अकादमी के विद्यार्थियों ने ड्रिल डम्बल की प्रस्तति दी। राजकीय मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कालका के विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार योग का प्रदर्शन किया। डीएसएम गत्खा खेल नर्सरी पिंजौर के सदस्यों ने गत्खा का प्रदर्शन किया।

11 स्कूलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी

गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूनिसन इंटरनेशन स्कूल पिंजौर के बच्चों ने दसों दिशाओं में लहरा रहा है अपना तिरंगा प्यारा समूह गीत गाया। अलपिन स्कूल के विद्यार्थियों ने हरियाणा नाच की प्रस्तुति दी। डीएवी सुरजपुर के विद्यार्थियों ने मंगल मिशन की रोचक झलक पेश की। अकाल जोत स्कूल के विद्यार्थियों पहाड़ी प्रस्तुति दी। सोफिया कॉवेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने जय जय जय भारत माता अविरल तेरी गौरव गाथा समूह गीत गाया।

संत विवेकानंद स्कूल पिंजोर के बच्चों ने बेटियों को बचाने की मारमिक प्रस्तुति दी, जिसे काफी सराहना मिली। सिख स्कूल के बच्चों ने हरियाणा नाच, आर्य स्कूल के बच्चों ने क्लासिक नाच पेश किया। आइसर स्कूल परवाणू के बच्चों ने नाच और नोबल स्कूल के हरियाणवी नाच की प्रस्तुति दी।

दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला : मंत्रिमंडल ने दिव्यांग पैंशन नियमों में दी संशोधन को मंजूरी

हरियाणा में अब 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांगजनों को भी मिलेगी पैंशन, 32000 दिव्यांग होंगे लाभान्वित

वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पैंशन का लाभ कर रही

चंडीगढ़, 23 जनवरी : हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पैशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया

मुख्यमंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए।इन 10 श्रेणियों को किया शामिलइन 10 श्रेणियों में प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास, वाक और भाषा दिव्यांगता, बहु–स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिका रोग, बहु–दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार और चिरकालिक तंत्रिका दशाएं शामिल है। वर्तमान में यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 208071 लाभार्थियों को दिव्यांग पैशन के रूप में 3000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। अब नियमों में शेष 10 दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार व्यक्ति इस पैशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

पीड़ितों के लिए आयु सीमा होगी

समाप्त बैठक में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है। यह भी निर्णय लियागया कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया व सिकल सैल एनेमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पैशन के अतिरिक्त होगी। सरकार की दिव्यांगजनों के कल्याण व स्वस्थ बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह सुनिश्चित करना है कि वे सुखद जीवन के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते रहें।

अब शुगर फ्री प्रॉडक्ट भी बनाएगा वीटा

वीटा उत्पादों की संख्या में होगी बढ़ोतरी, ब्रांडिंग पर रहेगा जोर

जींद के घी की होगी ब्रांडिग, प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी हुई चर्चा

करनाल में खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला होगी स्थापित

कैबिनेट मंत्री ने की हरियाणा डेयरी सहकारी फेडरेशन की समीक्ष, बैठक

चंडीगढ़ सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा अब शुगर फ्री प्रॉडक्ट भी बनाए, ताकि मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी इनकी उपलब्धता हो सके। उन्होंने हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन को निर्देश देते हुए कहा कि वीटा उत्पादों की संख्या में इजाफा करते हुए उनकी भरपूर ब्रांडिंग करे, ताकि यह उत्पाद जन–जन के दिल में अपनी गुणवत्ता के लिए स्थान बनाएं। उन्होंने जींद के घी की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए प्लांट क्षमता में बढ़ोतरी करने व घी के प्रचार–प्रसार में तेजी लाने की भी निर्देश दिए। आज हरियाणा सिविल सचिवालय पांचवे तल स्थित कांफ्रेंस कक्ष में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन के एमडी रोहित यादव, महाप्रबंधक व 6 वीटा प्लांटों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की। तकरीबन दो घंटे चली समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढाया जाएगा, ताकि आमजन की अधिक से अधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकें। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री प्रॉडक्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जींद प्लांट के घी की ब्रांडिंग की जाए। वीटा प्लांटों पर डिस्पले बोर्ड लगाते हुए सभी उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि खाद्य उत्पादों की जांच के लिए करनाल में केंद्र सरकार की योजना में राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला करनाल के हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस, एग्रो मॉल करनाल में स्थापित की जाएगी। इससे प्रदेश में लघु, सूक्ष्म व बडे उद्यमियों को लाभ मिलेगा और बेहतर तकनीक के साथ खाद्य उत्पादों की जांच समय पर हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूध उत्पादकों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ने आने दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर वीटा उत्पादों पर आमजन का भरोसा बढाना है, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर फेडरेशन के एमडी रोहित यादव, जीएम एसएस कोहली, संजय सेतिया, सीईओ विशंबर सिंह, चरण सिंह, राकेश काद्यान, नरेन्द्र धानिया, सुखदेव राज, कामिनी आदि उपस्थित रहे।

सहकारिता मंत्रालय 2024: विकास, नवाचार और समृद्धि की ओर बढ़ते कदम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नोन्द्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के सपने को मूर्त रूप देने के लिए 6 जुलाई, 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए विभिन्न पहलों और ऐतिहासिक कदमों को उठाया है। पिछले तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 56 प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इन पहलों पर अब तक हुई प्रगति और विवरण इस प्रकार हैं:

- **आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने 130 वर्षों में पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- **अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल** केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफईडी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन लिमिटेड (एनसीसीएफ) द्वारा विकसित पोर्टल का शुभारंभ किया।
- **आरसीएस और एआरडीबी के कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना** केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ किया।
- **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना।** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 24 फरवरी 2024 को गोदामों और अन्य कृषि संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पीएसीएस की आधारशिला रखी और 18,000 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया।

- **शहरी सहकारी बैंकों के लिए छतरी संगठन** केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छतरी संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।
- **एनसीओएल और यूओसीबी के बीच समझौता ज्ञापन** राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और उत्तराखंड आर्गेनिक्स कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी) के बीच 30 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **10,000 एमपीएसीएस, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियों का शुभारंभ** केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में डेबरी और मछली पालन सहकारी समितियों के साथ–साथ 10,000 नव स्थापित बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपीएसीएस) का उद्घाटन किया।

(ए) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

1. पीएसीएस को बहु–उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उप–नियम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय फेडरेशनों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद पीएसीएस के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए गए और 5 जनवरी 2023 को इसे जारी कर दिया गया।

- इन आदर्श उप–नियमों का उद्देश्य पीएसीएस/ एलएएमपीएस की आय के स्रोतों को बढ़ाना और डेयरी, मत्स्य पालन, भडारण आदि जैसे 25 से अधिक नए क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अब तक, 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने आदर्श उप–नियमों को अपना लिया है या उनके मौजूदा उप–नियम इस आदर्श उप–नियमों के अनुरूप है।

2 कम्प्यूटरीकरण के जरिए पीएसीएस को सुदृढ़ करना

- पीएसीएस/एलएएमपीएस का कम्प्यूटरीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में जारी रहा तथा क्रियाशील पीएसीएस/ एलएएमपीएस को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के जरिए नाबार्ड से जोड़ा गया।
- अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पीएसीएस के कम्प्यूट्रीकरण के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद, डिजिटलीकरण तथा सहायक प्रणालियों की स्थापना के लिए राज्यों को कुल 700.42 करोड़ रुपए तथा नाबार्ड को 165.92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18,000 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का उद्घाटन किया।

3. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहु–उद्देशीय पीएसीएस/ डेयरी/ मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी, 2023 को इस योजना को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश की सभी पंचायतों/ गांवों को शामिल करते हुए नई बहु–उद्देशीय पीएसीएस, डेयरी, मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना करना है।
- यह योजना नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करके लागू की जा रही है।
- योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 19 सितम्बर, 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) भी शुरू की गई, जिसमें लक्ष्य, समयसीमा और संबंधित हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ बताई गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 10,825 नई एम–पीएसीएस, डेयरी और मछली पालन संबंधी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे 31 मई, 2023 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वये के माध्यम से पीएसीएस स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे, जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि का निर्माण करना शामिल है।
- केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और पीएसीएस स्तर पर ही विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए इस परियोजना पर विशेष बल दे रहे हैं।
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों के 11 पीएसीएस में गोदामों का उद्घाटन किया गया और 500 अतिरिक्त पीएसीएस में गोदाम निर्माण की आधारशिला 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई।

5. ई–सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पीएसीएस

- सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई–गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 2 फरवरी, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि पीएसीएस को सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली 300 से अधिक ई–सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। सीएससी–एसपीवी और नाबार्ड के समन्वय में एनसीसीटी द्वारा इन पीएसीएस को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
- अब तक 41,075 पीएसीएस ने सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है और इन पीएसीएस के जरिए 60 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस परियोजना का उद्घाटन किया। देश के सभी क्रियाशील पीएसीएस/एलएएमपीएस के माध्यम से

सीएससी सुविधाएं प्रदान करने की योजना है, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

6. पीएमीएस द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

- एफपीओ योजना के तहत सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 1100 अतिरिक्त एफपीओ आवंटित किए गए हैं। अब पीएसीएस, एफपीओ के रूप में, कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियां कर सकेंगे। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक बाजार संपर्क उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी।

खुशहाल प्रदेश, समृद्ध गांव सहकारिता द्वारा

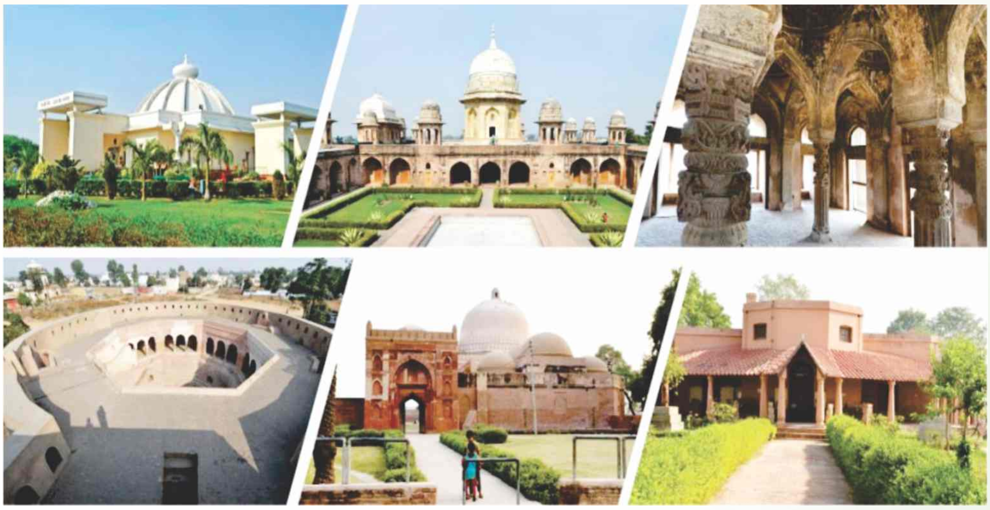

कृषि प्रधान हरियाणा के गावों को यहां की अर्थव्यवस्था का प्राणाधार कहा जाएगा। गांवों की समृधि को ही प्रदेश की खुशहाली बसती है। सरकार ग्रामीण विकास की दिशा में सत्त प्रयासरत है। अब सहकारिता आन्दोलन को सफलता देने के प्रयास किये जा रहें हैं। लोगों के समूह द्वारा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का ठोस जतन है सहकारिता आन्दोलन। काम करो के नारे के साथ भारत वर्ष में चलाये जा रहे इस आन्दोलन के उद्देश्य की व्यापकता को सहकारिता आन्दोलन के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जा सकता है। इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं है। सहकारी समितियां आर्थिक रूप से सम्पन्न होगी तो ही गावों की अर्थिकी की सशक्त होगी।

गांवों में प्रतिस्पर्धी बहुउद्देशीय सहकारी समिति (सीएम पैक्स) खुलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि एवं वाणिकी दोनों की स्तर पर लाभ मिलेंगे। सीएम पैक्स का उद्देश्य की प्रदेश के सभी गावों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने का है तथा सुस्त पड़े कुटीर उद्योगों को आर्थिक आधार मिलेगा तो ग्रामीण विकास को नया आयाम मिलेगा। हर गांव में सीएम पैक्स खोले जाने का माननीय प्रधानमन्त्री व केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री जी का सपना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमन्त्री जी और सहकारिता मन्त्री ने हर गांव में सी.एम.पैक्स खोलने की योजना तैयार की है। प्रधम चरण में 500 गांवों में सी.एम.पैक्स खोल कर मार्च तक इनको संचालित करने की योजना तैयार की है। ये पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों और गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों के सहयोग से कार्य करेगी सी.एम.पैक्स में कम से कम 11 सदस्य व अधिकतय कितने भी सदस्य हो सकते है। सरकार ने हिस्सा पूजी बीस हजार से घटाकर एक हज़ार रूपये प्रति सदस्य कर दी है। उक्त पैक्स अनाज गौदाम, पट्रोल पम्प,खाद्य वस्तुएं बनाने व कुटीर ,उद्योग स्थापित कर सकेंगी लाभांश में सभी सदस्यों की बराबर हिस्से दारी रहेगी। ये पैक्स कम्पनियों की तरह कार्य करेगी। केन्द्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसकों माननीय मुख्यमन्त्री जी व सहकारिता मन्त्री ने हरियाणा में लागू करने में विशेष रूचि दिखाई है।

देवेन्द्र सिंह सिवाच
सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी
भिवानी/हिसार हरकोफैड

युवा उत्थान में सहकारिताओं की भूमिका

युवा उत्थान में सहकारिताओं की भूमिका निम्नलिखित प्रकार है :–

अह्म साह्किरता : सयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियमित करता है और उनके माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं व अकाक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक व एकजुट व्यक्तियों का स्वाय संघ है। इसके आलावा इसके तीन स्तरीय होते है जैसे :– (1) एक संगठन की स्वैच्छिक होती है और उन पर कोई बाहरी दबाव नही होता (2) इनका का प्रबंधन जनतात्रिक के आधार पर होता है।

युवा उत्थान में सहकारिता की अहम भूमिका :–

1. युवाओं के लिए सहकारी उद्यमों और काम करने के लिए मौका मिलता है। सहकारी समितियों में युवा ऊर्जा और गतिशील से नए कार्य पैटर्न और नवाचार को बढ़ावा मिलता है

2. युवाओं को अपने सिद्वान्त और प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

3. सहकारी क्षेत्र में नई ऊर्जा को भरने में मदद मिलती है।

4. युवा सहकारिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम युवा सहकार योजना है समुदाय के विकास में भूमिका निभाती है।

5. सहकारी समितियाँ वचित समुदाय को उनकी बुनियादी जरूरतों तक पहुँचती है।

सहकारिता पर युवा समिति :- ज्ञान, विचारों और अनुभवो को आदान–प्रदान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देकर सीमित और युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसरों में सुधार करने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और व सामाजिक सुरक्षा की वकालत करने की दिशा में काम करती है और युवाओं का समाज में एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे देश में एक विकास के लिए निर्णायक होता है।

युवा सहकार :- सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा देश भर में सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सावर्धिक सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारम्परिक सहायता पर आधारित बैंकिग संस्थाओं और उनका स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं सगंठित कर उनका विकास करता है।

सहकारिता का उदेश्य :- कला, उत्पादन या डेयरी उत्पादन बेचना हो सकता है या फिर इटरनेट किराने का समान बिजली तक पहुँच में सुधार करना हो सकता है।

सहकारिता के जनक कौन थे :– सहकारिता समिति एक व्यवसाय है सहकारी समितियों की शुरूआत के बहुत सारे रिकार्ड मौजूद है यथापि रोशडेल पायनिवर्स को आमतौर पर आधुनिक सहकारी समिति का प्रोटोटाइप और 1884 में सहकारी आदोलन के संस्थापकों के रूप में माना जाता है। इस वर्ष अंतराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई 2021 को बेहतर पुननिमार्ण के रूप में मनाया जा रहा है।

सहकारिता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए अनुमती देती है।

सहकारिता का अर्थ :- सहकारिता दो शब्दों के मेल से बना है सह + कारिता जिससे सह से आश्य है / मिल झुलकर साथ–साथ कारिता का अर्थ कार्य करना इस प्रकार मिलजुल साथ–साथ काम करना सहकारिता यह ऐसा संगठन है जिसके सदस्य समानता के आधार पर है पारम्परिक हितों के लिए मिलजुल कर कार्य करते है।

सहकारी समाज में युवाओं की भूमिका :- क्योंकि यह एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाते है रचनात्मक कौशल का विकास युवा सहकारी संगठन है विकास के लिए रचनात्मक कौशल का विकास युवा और गतिशील होते है तथा नए विचारों से प्रेरित होता है। 1 साथ मिलकर काम करना 2 आगे बढ़ना 3 अर्थ खोजना।

बच्चे देश का भविष्य

भारत की आजादी के कुछ साल बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से कार्यक्रम में छोटे से गांव में आए, नेहरूजी के आने की खबर गांव में फैल गई और हर कोई उन के स्वागत के लिए उत्सुक था, खास कर बच्चे काफी उत्साहित थे कि उन के प्यारे चाचा नेहरू उन से मिलने आ रहे हैं,

गांव की एक छोटी सी लड़की माला उन से मिलने के लिए काफी बेचैन थी, उस ने अपनी मां से कहा, '' मां, मैं चाचा नेहरू को फूलों की माला पहनाना चाहती हूं और उन्हें अपनी किताबें दिखाना चाहती हूं''

माला के पापा मजदूर थे, माला को पढ़ने का बहुत शौक था, हालांकि उस के पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन जो कुछ थीं, उन्हें वह संभाल कर रखती थी, कार्यक्रम वाले दिन नेहरूजी गांव पहुंचे, लोग उन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे और बच्चे उन की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े माला भी भीड़ के बीच से निकली, लेकिन नेहरूजी के नजदीक पहुंचने में उसे काफी मुश्किल हुई, तभी नेहरूजी की नजर उस के छोटे हाथों में कस कर पकड़ी किताबों के बंडल पर पड़ी।

''रूको, उस बच्ची को मेरे पास आने दो,'' नेहरूजी ने अपने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया,

यह देख कर माला कुछ घबराई, लेकिन रोमांचित हो कर वह धीरे–धीरे नेहरूजी के पास रोमांचित हो कर वह धीरेधीरे नेहरूजी के पास पहुंची, खुशी से कांपते हुए उस ने फूलमाला नेहरूजी के गले में डाल दी, नेहरूजी ने गर्मजोशी से मुसकराते हुए उस के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, ''तुम्हारे पास ये किताबें क्यों हैं, बेटी ?''

धीमी आवाज में माला ने जवाब दिया, '' चाचा नेहरू, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं हैं, मैं यह किताबे आप को दिखाने के लिए लाई हूं''

नेहरूजी उस की बात सुन कर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, '' पढ़ाई के प्रति तुम्हारी लग्न इस देश का भविष्य है, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन महान विद्वान बनोगी।''

उन्होंने उस से वादा किया कि वे उस के स्कूल में कुछ किताबें भिजवाएंगे, ताकि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

कार्यक्रम में नेहरूजी ने अपने भाषण में बच्चों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, ''बच्चे इस देश का भविष्य हैं, यदि हम उन्हें अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल होगा, हमें हर बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए, जिस से वह अपने सपने पूरे कर सके।''

नेहरूजी के इस भाषण के बाद सब को महसूस हुआ कि चाचा नेहरू केवल एक नेता नहीं, बल्कि हर बच्चे के सच्चे अभिभावक भी थे, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वे जानते थे कि नेहरू ने उस के सपनों को साकार करने की कोशिश कर दी हो।

स्कूल में नई किताबें आने से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उस छोटी बच्ची से ज्यादा खुश

कोई और नहीं था। अब उस का सपना डाक्टर बन कर अपने गांव के लोगों की सेवा करना था।

चाचा नेहरू के शब्दों से प्रेरित हो कर वह हर दिन स्कूल जाते समय उन के शब्दों को याद करती थी, ' तुम्हारा पढ़ाई के प्रति जुनून ही इस देश का भविष्य है'

चाचा नेहरू के प्यार और प्रोत्साहन ने कई और बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्ररित किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी जब उम्र और बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ही सीमित कर दिया था। फिर भी उन का दिल देश और दुनिया के लोगों के लिए धड़कता था और वे हमेशा की तरफ उत्साह और जोश से परिपूर्ण थे।

एक दिन उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ कॉलेज के छात्रों ने उन से एक विशेष ट्रॉफी की मांग की है। इसे एक साधारण अनुरोध के रूप में टालना आसान होता, लेकिन नेहरूजी के लिए यह सिर्फ एक ट्राफी नहीं थी, बल्कि यह उन छात्रों की उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक था, जिसे वे किसी भी सूरत में टूटना नहीं देना चाहते थे।

नेहरूजी ने अपनी बीमारी के बावजूद अपने सहायकों से कहा, ''महत्वपूर्ण यह है कि ट्रॉफी समय पर आस्ट्रेलिया के छात्रों तक पहुंच जाए, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते।''

भारत की आजादी के बाद देश ने विभाजन, धार्मिक संघर्ष और सामाजिक मतभेदों के कठिन दौर का सामना किया, लेकिन एक व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने चुनौतियों से भरे इस नए भरे इस नए भारत को एक सूत्र में पिरोने के अथक प्रयास किए।

नेहरू का मानना था कि आजादी के बाद हर भारतीय को सब से पहले एक भारतीय के रूप में पहचानना चाहिए, न कि जाति, धर्म और राज्य के आधार पर।

एक बार एक सभा में उन्होंने कहा, ''मैं भले ही एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा पहला और सब से बड़ा धर्म मेरा देश है।''

उन का मानना था कि हर भारतीय का धर्म और जाति से ऊपर उठ कर देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए, खुद को 'भारतीय' बता कर नेहरूजी ने देश की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत विश्वास था और उन का मानना था कि यह देश को प्रगति और समृद्धि की ओ ले जाएगा।

एक वैज्ञानिक सम्मेलन में नेहरूजी ने कहा , ''भारत का भविष्य केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत विश्वास था और उन का मानना था कि यह देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा।

एक वैज्ञानिक सम्मेलन में नेहरूजी ने कहा, ''भारत का भविष्य केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर ही हो सकता है। यदि हम विज्ञान को समझेंगे, तो हम खुद को और दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।''

नेहरूजी ने भारत को वैज्ञानिक सोच के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। उन के मार्गदर्शन में भारत ने अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की और यह दृष्टि देश को वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। वे न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि देश के हर नागरिक के चाचा भी थे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल विविधीकरण और गुणात्मक इनपुट तथा कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदर्भ में उत्पादन पहलुओं जैसे महत्वर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के कल्याण के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू की प्रमुख उपलब्धियां:

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि- 2024–25 के दौरान किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत 122528.77 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

2. रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन- तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023–24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन 332.30 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जबकि बागवानी उत्पादन 352.23 मिलियन टन है।

3. पीएम-किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता-पीएम–किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण–डीबीटी के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6,000 रूपये प्रति वर्ष हस्तांतरित किए जाते हैं। यह योजना तकनीकी और प्रक्रिया प्रगति का लाभ उठाती है ताकि अधिकतम लाभार्थी बिना किसी परेशानी के लाभान्वित हो सकें। पीएम–किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। 18 किस्तों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थी किसानों को कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है।

4. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)- रु.1 लाख करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक खेती के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओ के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। यह 7 वर्षों तक के लिए रु.2 करोड़ तक के ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता और सीजीटीएमएसई योजना के माध्यम से रु.2 करोड़ तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करता है। 2020 में अपनी स्थापना के बाद से, एआईएफ ने 84,159 परियोजनाओं के लिए रु.51.364 करोड़ मंजूर किए हैं। इनमें गोदाम, प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कटाई के बाद की सुविधाएं मिल हैं। 28.08.2024 को सरकार ने सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां को एकीकृत करने, द्वितीयक प्रसंस्करण और पीएम–कुसुम घटक–ए के साथ अभिसरण सहित एआईएफ के दायरे का विस्तार करने के उपायों को मंजूरी दी। इन पहलों का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, इनपुट लागत को कम करना, उत्पादकता मंम सुधार करना और कृषि आय में वृद्धि करना है। जिससे भारत में सतत कृषि विकास का समर्थन हो सके।

5. एफपीओएस को बढ़ावा - 29 फरवरी 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई, 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का बजट 2027–28 तक रु. 6,865 करोड़ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाबार्ड, एसएफएसी, नेफेड और अन्य सहित 14 एजेंसियों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है। आवंटित 10,000 एफपीओ में से 9,180 पंजीकृत हो चुके हैं।

6. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना -सरकार ने 2018–19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। 2023– 24 में धान (सामान्य) के लिए एमएसपी रु.2,300 प्रति क्विटल निधर्धारित किया गया है, जबकि गेहूं के लिए एमएसपी बढ़ाकर 6.2,425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि–2024–25 के दौरान 122528.77 करोड़ रुपये की राशि

पीएम–किसान पीएम– किसान के माध्यम से किसानों को आप सहायता

2023–24 में धान (सामान्य) के लिए एमएसपी रु. 2.300 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि गेहूं के लिए एमएसपी बढ़ाकर रु. 2.425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत रु. 1.70 लाख करोड़ से अधिक दावों का भुगतान किया गया है और

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण– कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण वितरण में 349 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013–14 में रु. 7.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2021–22 में रु. 1,425 हो गई है। वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 25.48 लाख करोड़

डिजिटल कृषि मिशन, 02.09. 2024 को रु. 2,817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत

23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1410 मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत किया गया

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन–तिलहन (एनएमईओ–तिलहन) का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ यह 2024

7. नमो ड्रोन दीदी योजना- सरकार ने किसानों को उर्वरक और कीटनाशक लगाने जैसी किराये की सेवाएं देने के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1.261 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। 2023–24 में, 500 ड्रोन खरीदे गए (स्वयं के संसाधनों से) और लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा वितरित किए गए। शेष 14,500 ड्रोन 2024–25 और 2025–26 में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य स्थायी व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है, जिसमें एसएचजी को सालाना कम से कम 1 लाख रुपये की कमाई हो।

8. प्रति बूंद अधिक फसल–2015–16 में शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिचाई तकनीकों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। शुरुआत में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत लागू किया गया, यह अब 2022–23 से आरकेवीवाई का हिस्सा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत और अन्य को 45 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015–16 से 2024–25 (दिसंबर 2024) तक लगभग 95 लाख हेक्टेयर को कवर किया गया है। 2020–21 में नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में पाया गया कि पीडीएमसी जल उपयोग दक्षता (30 से 70 प्रतिशत) में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि (10 से 69 प्रतिशत) और रोजगार के अवसर सृजित करने में प्रभावी है।

9. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण- कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण वितरण में 349 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013–14 में रु.7.30 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 25.48 लाख करोड़ हो गया है। इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण शामिल है। उल्लेखनीय रूप से अल्पकालिक ऋणों में भी 275 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वित्त वर्ष 2013–14 में रु 5.48 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में रु.15.07 लाख करोड़ हो गया है। यह पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अल्पकालिक ऋण निवेश 270 प्रतिशत बढ़कर रु.3.63 लाख करोड़ से रु.9.81 लाख करोड़ हो गया है।

10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)- 2016 में शुरू पीएमएफबीवाई प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं के कारण फसल के नुकसान पर व्यापक कवरेज प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत रु.1.70 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। कृषि रक्षक पोर्टल (केआरपीएच) और एक समर्पित टोल–फ्री हेल्पलाइन (14447) कुशल शिकायत निवारण के लिए स्थापित की गई है। इससे किसान शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं।

11. ई-नाम प्लेटफॉर्म की स्थापना - विभाग ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1410 मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत किया है। 31.12.2024 तक 1.78 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी ई–नाम पोर्टल पर पंजीकृत है। कुल 11.02 करोड़ मीट्रिक टन और 42.89 करोड़ नंबर (बांस, सुपारी, नारियल, नीबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 4.01 लाख करोड़ रुपये का व्यापार ई–नाम प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

12. डिजिटल कृषि मिशन - केंद्रीय बजट 2023–24 में सरकार ने कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के विकास की घोषणा की, जिसे 2024–25 के बजट में और बढ़ाया गया। डीपीआई किसानों पर व्यापक डेटा प्रदान करेगा। इसमें जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलें शामिल हैं। यह अभिनव, किसान केंद्रित सेवाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के डेटा को एकीकृत करती हैं। 02.09.2024 को रु.2.817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन पहल के मूल में तीन प्रमुख डीपीआई शामिल है। एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), और मृदा प्रोफाइल मानचित्रण। एग्रीस्टैक 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी बनाएगा और एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करेगा। डीएसएस फसलों, मिट्टी, मौसम और पानी पर भू–स्थानिक डेटा को एकीकृत करेगा, जबकि मृदा प्रोफाइल मानचित्र 142 मिलियन हेक्टेयर को कवर करेगा। मिशन में सटीक उपज अनुमानों के लिए डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य 2,50,000 प्रशिक्षित युवाओं और कृषि सखियों के लिए रोजगार सृजित करना तथा एआई और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किसानों को सेवा प्रदान करना है।

13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना - 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) कार्यक्रम राज्य सरकारों को किसानों को एसएचसी जारी करने में सहायता करते हैं। 2022–23 से, उन्हें आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता घटक के अंतर्गत मिला दिया गया। 2024–25 की उपलब्धियों में शामिल हैं:

- 75 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए, 92 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 53 लाख एसएचसी बनाए गए।
- आबंटित 201.85 करोड़ रुपये में से 109.87 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- 1,020 स्कूलों में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं और 125,972 छात्रों का नामांकन हुआ है।
- 31 लाख किसानों को एटीएमए से मृदा स्वास्थ्य सलाह मिली।

14. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू किया है। इस योजना का कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये है।

15. आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक - आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक, जो मूल रूप से 2016–17 से 2021–22 तक कृषि वानिकी पर उप–मिशन (एसएमएएफ) का हिस्सा है। यह अतिरिक्त किसान आय के लिए खेत पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है। इस अवधि में 1.21 लाख हेक्टेयर में 532.298 लाख पेड़ लगाए गए और 899 नर्सरी स्थापित की गई। इसमे लगभग 1.86 लाख किसान लाभान्वित हुए। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों द्वारा नर्सरी की स्थापना का समर्थन करने के लिए 2023– 24 में योजना का पुनर्गठन किया गया। 2023–24 में 162 नई कृषि वानिकी नर्सरियों के लिए रु.58. 10. करोड़ जारी किए गए और 470 मौजूदा नर्सरियों ने पौधे उगाना शुरू कर दिया। 2024–25 में 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 33.24 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें दिसंबर 2023 में नर्सरियों के लिए मान्यता प्रोटोकॉल विकसित किए गए। अब तक 133 नर्सरियों को मान्यता दी जा चुकी है।

16. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) - आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) का उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और 'मीठी क्रांति' हासिल करना है। 2020–23 के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस योजना को 370 करोड़ रुपये शेष रहते हुए 2025 तक बढ़ा दिया गया था। यह एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, मधुमक्खी पालन उपकरण निर्माण इकाइयां और कस्टम हायरिंग केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए तीन मिनी मिशनों (एमएम–1, एमएम–2, एमएम–3) पर केंद्रित है। प्रमुख उपलब्धियों में 8 क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, 33 शहद प्रसंस्करण इकाइयां, 1305 हेक्टेयर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, 385 हेक्टेयर मधुमक्खी–अनुकूल वृक्षारोपण शामिल हैं।

17. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) 2014–15 से 2024–25 तक, एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है: 13.96 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों का विस्तार किया गया, 908 नर्सरियां स्थापित की गई. 1.52 लाख हेक्टेयर पुराने बागों का कायाकल्प किया गया और 52.459 हेक्टेयर जैविक खेती के अंतर्गत कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, 3.08 लाख हेक्टेयर संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किए गए, 55,347 जल–संचयन संरचनाएं बनाई गई और 16.45 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया। इसके अलावा, 9.77 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया। योजना में हाल के बदलावों में राष्ट्रव्यापी कवरेज, मखाना और औषधीय फसलों को शामिल करना, और एफआरए पट्टा भूमि और लाख कीट मेजबान पौधों के बागानों वाले आदिवासी परिवारों को लाभ प्रदान करना शामिल है।

18. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - तिलहन (एनएमईओ–तिलहन)–खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन तिलहन (एनएमईओ–तिलहन) का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह 2024–25 से 2030–31 तक चलेगा। मिशन का लक्ष्य 2030–31 तक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022–23) से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है। इस पहल से उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों, चावल की परती खेती और अंतर फसल को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य 2030–31 तक घरेलू खाद्य तेल की 72 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करना है।

19. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना: 2014–15 में शुरू की गई कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एसएमएएम) कृषि मशीनरी खरीदने और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), हाई–टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपलब्धियाँ (2014-15 से 2024-25, नवंबर 2024 तक):

- राज्यों में 8,565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- ट्रैक्टर और पावर टिलर सहित 19,09,809 कृषि मशीनें वितरित की गई।
- 26,637 सीएचसी, 609 हाई–टेक हब और 24,176 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए।
- किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें आईसीएआर को 296 ड्रोन खरीदने के लिए 52.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- किसानों को 527 ड्रोन दिए गए और 1.595 ड्रोन सीएचसी स्थापित किए गए।
- आईसीएआर ने 287 कर्मियों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है।
- 30.234.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 27,099 ड्रोन प्रदर्शन किए गए, जिससे 3,51,856 किसान लाभान्वित हुए।

20. 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना (नवंबर, 2024 तक): 2018–19 में शुरू की गई फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना, वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देने में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सहायता करती है।

उपलब्धियाँ:

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आईसीएआर को 4,391.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- 3,19,103 इन–सीटू अवशेष फसल प्रबंधन मशीनें वितरित की गई।
- 40,996 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए।
- 2023 की तुलना में 2024 के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 57 प्रतिशत की कमी आई है।

21. जलवायु लचीली किस्में - बाढ़/जल डूब/जल भराव सहनशीलता, सूखा/नमी तनाव/जल तनाव सहनशीलता, लवणता/क्षारीयता/सोडियम मिट्टी सहनशीलता, ताप तनाव/उच्च तापमान सहनशीलता, ठंड/ठंढ़/सर्दियों में ठंड सहनशीलता सहित चरम जलवायु के लिए विशेष रूप से अनाज, तिलहन, दलहन, चारा फसलों, फाइबर फसलों और शर्करा फसलों की जलवायु लचीली फसल किस्मों को सटीक फेनोटाइपिंग उपकरणों का उपयोग करके विकसित किया गया है। आईसीएआर ने हाल ही में 109 जलवायु लचीली किस्में जारी की हैं जो किसानों को कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाने में मदद करेंगी।

22. विस्तार सुधार (एटीएमए) योजना - एटीएमए, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्तमान में देश 1 के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में लागू किया जा रहा है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और किसान–अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फार्म स्कूल आदि के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीक और अच्छी कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराना है।

सरकार के सभी प्रयास और पहल कृषक समुदाय को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं।

कहानी
धरती माँ है रे............

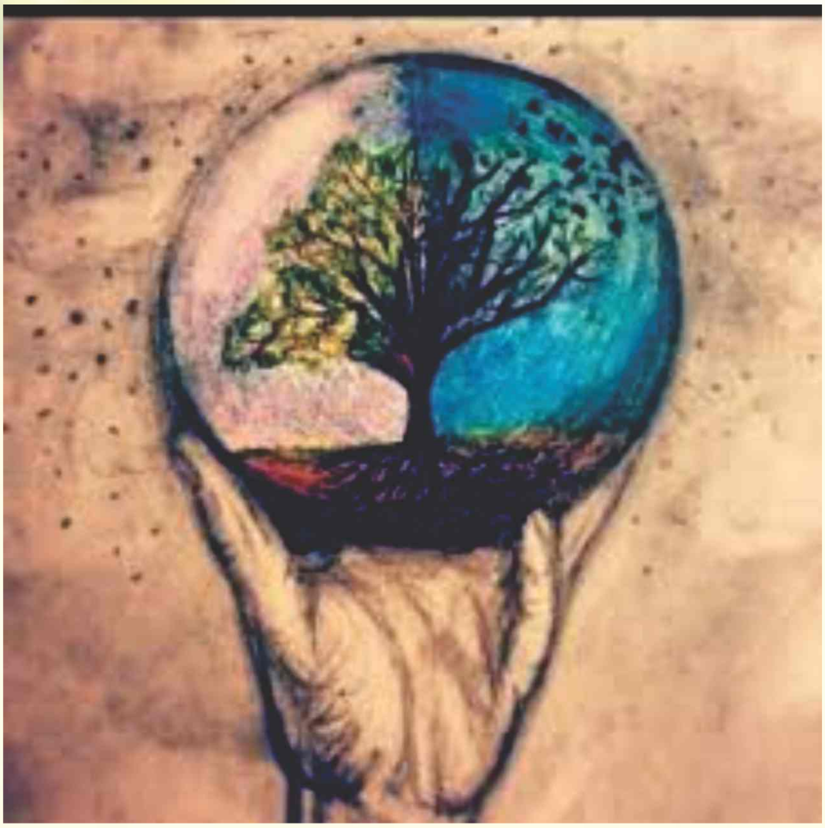

किशना बादलों को टकटकी लगाए देख रहा था। उमड़ते–घुमढ़ते बादलों को देखते हुए उसकी आंखों में आशा के दीप जल उठे। छाई हुई घनघोर घटा से मन पूर्णिमा के चांद की भांति उज्जवल हो गया। ठंडी–ठंडी वायु सांसों में रस घोलने लगी। एका एक वायु की गति अति तीव्र हो गई। पुलकित मन शंका से भर गया कहीं आंधी तो नहीं आ रही... पल भर में ही मंजर बदल गया। जो वायु सांसों में रस घोल रही थी उसी वायु में अब खुद को संभाल कर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आंधी बादलों को अपने संग ले उड़ी। किशना ने बाहें फैला कर बादलों को पकड़ना चाहा लेकिन...।

आकाश में छाए हुए बादल जितना सुख देते थे उससे कहीं अधिक दुःख में डूब जाता था। किशना, जब वायु उन बादलों को बरसने से पहले ही अपने संग कहीं दूर उड़ा ले जाती। खेती के लिए जितना आवश्यक बीज है उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है जल, यदि जल ही न हो तो खेती की उम्मीद कैसे करे..., हरियाली कहां से आए..., किशना सोचने लगा बस कुछ दिनों की बात है उसका पुत्र विवेक शहर से कृषि की पढ़ाई पूरी करके आने ही वाला है। शहर से आकर वह उसकी इच्छा जरूर पूरी करके आने ही वाला है। शहर से आकर वह उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसकी इच्छा थी खेतों को दूर तक हरा–भरा देखना, फसल पकने के बाद खेतों को सोना उगलते देखना बस... एक बार देख लेगा तो अंतिम सांस सुख से ले सकेगा। किशना को पूर्ण विश्वास था कि विवेक अपने विवेकी स्वभाव होने के कारण परिश्रम, लगन एवं मेहनत से अपने खेतों को तो क्या, गांव के सभी खेतों को

हरा–भरा कर देगा। आंधी के पश्चात चहुं और शांत वातावरण था उसी प्रकार उसका मन भी शांत था।

उत्साहित कदमों को लिए वह घर की तरफ चल दिया। जैस–जैसे कदम घर की ओर बढ़ रहे थे उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। जैसे ही उसने घर के भीतर कदम रखा, मुनिया का दिल कांप उठा ये सोचकर कि आज बादल बिन बरसे ही चले गए लेकिन किशना उस पर किसी न किसी कारण क्रोध से जरूर बरस पड़ेगा। वर्षों से ऐसा ही होता आया है। परंतु ये क्या ? आज किशना का चेहरा वर्षा से ऐसा ही होता आया है। परंतु ये क्या ? आज किशना का चेहरा वर्षा ने होने के कारण भी फूल की भांति खिला हुआ है। इससे पहले कि वह पूछती किशन बोल उठा– " मुनिया, अब इन बादलों की तरह हमारे दुः ख के दिन भी चले गए। अपना विवेक आएगा, खेती–बाड़ी संभालेग। जानती हो ? सरकार ने खेती का बढ़ाने के लिए नए–नए कार्यक्रम शुरू किया हैं। हमारा विवेक सरकार के साथ मिल कर हरित–क्रांति लाएगा गांव में, चहुं ओर हरियाली ही हरियाली होगी। मुनिया ने भी उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा – " आखिर बेटा किसका है ? "किशना ने छाती ठोक कर कहा – "मेरा"

मुनिया उसकी इस अदा पर शरमा गई और कोई उलाहना भी न दे सकी।

सुबह का सूरज लालिमा–युक्त था प्रतिदिन की तरह लेकिन किशना को पता नहीं क्यों आज का सूरज नया–नया–सा लगा उसके मन में आशा की किरण ठीक उसी प्रकार प्रवेश कर रही थी जिस प्रकार कमरे की खिड़की से सूरज की किरण।

किशना ने मुनिया से कहा – " आज सूरज नया–नया लग रहा है ना ? "

"क्यों नहीं लगेगा ? आज अपना विवेक जो आ रहा है पढ़ाई पूरी करके", मुनिया ने प्रत्युत्तर में कहा।

तभी विवेक ने घर में प्रवेश किया। माता–पिता की आँखें नम हो उठी। गाल पर लुढ़के आंसू शरीर तो क्या आत्मा तक को सुख रूपी स्नान करवा रहे थे। आते ही खाना खाकर विवेक खेतों की तरफ चल पड़ा। पिता का सीना गर्व से फूल गया। अनायास ही मुख से शब्द फूट पड़े – " देखा कितनी चिन्ता है बेटे को खेत की, अब मेरे दिन आराम करने के आ गए। बेटा अपनी धरती माँ को स्वयं संभालेगा। यह कह कर उसने सुख की सांस ली।

खेत पर जाकर विवेक ने सोचा हमारे खेत शहर से अधिक दूर नहीं हैं। कीमत तो अच्छी मिलेगी ही, बिना मेहनत के ही इतना सारा धन.... वाह.... बाबा ने सपने में भी इतनी धन राशि देखी नहीं होगी। उसने दिल ही दिल में एक निर्णय लिया और डीलर से बात भी कर ली। सोच रहा था बस बाबा के हस्ताक्षर होने की देर है फिर पैसा ही पैसा होगा। बात एवं रकम पक्की करके खुशी–खुशी घर वापिस आ गया, मां–बाबा तो खुश ही थे, विवेक उससे भी कहीं अधिक खुश था। हां तीनों की खुशी खेतों को लेकर, विवेक धन को लेकर, ये तीनों उसी तरह जुड़े थे जिस प्रकार कमरे की तीन दीवारें, एक दूसरी दीवार से जुड़ी थी, लेकिन खुशियां अलग थी इन तीन दीवारों की तरह ही, जो जुड़ी होने के बाद भी अलग थी।

विवेक सोच रहा था, बाबा से खेत बेचने की बात कैसे करें ? न जाने बाबा की क्या प्रतिक्रिया होगी ? आखिर बात करने का एक सिरा उसे हाथ लगा। सिरे को पकडते हुए उसने का– बाबा सारी उम्र इस खेत में काम करके दो समय का खाना भी ढंग से नसीब नहीं हुए। .... जानते हो हमारे खेत सोना है सोना.....ये खेत हमारी झोंपड़ी को महल में तबदील कर सकते हैं। ....धप की बरसात कर सकते हैं।"

किशना ने कहा– "क्यों नहीं, अब तू जो संभालेगा इन खेतों को, धन की बरसात तो होगी ही... मैं अनपढ़ गंवार क्या खेती संभालता ?"

विवेक ने बात का दूसरा सिरा पकड़ते हुए कहा – " बाबा मेरी बात का बुरा मत मानना, बुद्धिमान वही होता है जो समयनुसार स्वयं को ढ़ाल सके, मेरी मानों तो इन खेतों को बेच दो, शहर के नजदीक होने के कारण ...." विवेक की इतनी सी बात सुन कर किशना क्रोध से कांपने लगा, आँखों से नदिया बह चली, जैसे आज ही उसे रास्ता मिला हो। मन पर शब्दों की बौछार हो रही थी लेकिन गल से बाहर नहीं आ रहे थे, कुछ न कह सके, बस शुन्य की ओर ताकने लगे आँखें पथरा गई।

लम्बी खामोशी को तोड़ते हुए विवेक ने कहा – " बाबा.... । मेरा निर्णय क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा...? प्रत्युत्तर में बस इतना ही कहा – "बेटा यदि मैं तेरी मुनिया माँ को बेच दूं, जिसने तुम्हारा लालन–पालन किया ? तुझे अच्छा लगेगा ? ... जैसे मुनिया तेरी माँ है उसी प्रकार धरती, ये खेत मेरी मां है रे... जो मेरा ही नहीं हम सब का लालन–पालन करती है।" फिर थोड़ा रूक कर बोला – " आज कुछ लोग धरती को बेच कर बड़े–बड़े उद्योग बना रहे हैं, उद्योगों से सब कुछ पैदा किया जा सकता है अन्न के। आज मानव की अन्न पहली जरूरत है। यदि यही ना हो तो जीवन कहां रहेगा। तुम खेतों को बेचकर स्वयं को सुखी बना सकते हो लेकिन हम किसान स्वयं के लिए नहीं जीते, दूसरों को जीवन देने के लिए जीवित रहते हैं। यह धरती हम सब की माँ है हम किसान अपनी माँ को बेचकर कैसे सुखी रह सकते हैं ? यह कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा गई...... आगे एक भी शब्द न बोल सका..."

मुझे माफ कर दो बाबा... मेरी उच्च शिक्षा से कहीं बेहतर है तुम्हारी वह शिक्षा जो परंपराओं ने तुम्हें दी है, जीवन और व्यापार ने सिखाई है। किसान का बेटा हूं खेतों का व्यापार करके व्यापारी न बन सकूंगा। किसान ही रहूंगा। क्योंकि धरती हमारी मां है बाबा...." इतना कहकर वह बाबा के पैरों में गिर पड़ा

SAHKAR SE SAMRIDDHI
Aatmanirabhar Bharat, Aatmanirbhar Krishi
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO NANO UREA Plus
and
IFFCO NANO DAP
Promises
More Yield And More Profit
World's First Nano Fertilizer by IFFCO
500 ML Bottle ₹225/- only
500 ML Bottle ₹600/- only
Contains 20% NITROGEN
FREE ACCIDENT INSURANCE
IFFCO Nano UREA Plus Liquid
NANO UREA PLUS
Chlorophyll Charger
Yield Booster
Climate Smart Farming
NANO DAP
LIQUID (8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Seed Primer | Growth Enhancer | Yield Booster
Less Cost, More Profits
IFFCO Nano DAP Liquid
INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED
IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones: 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website: www.iffco.coop

श्री गुरू गोबिंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग मुख्यालय पर लंगर का आयोजन किया गया। प्रशाद वितरण में अपनी सेवा देते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल, भा.प्र.से।

सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, गोहाना श्री प्रशांत को 76वें गणतंत्र दिवस पर गोहाना में सम्मानित करते विधायक सोनीपत श्री निखिल मदान एवं गोहाना एस.डी.एम श्रीमती अंजली शिरोतिया, भा.प्र.से।

76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरजकुण्ड, फरीदाबाद के राजहंस होटल में एट होम कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल, हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री हरविन्द्र कल्याण एवं माननीय सहकारिता, कारागार, निर्वाचन एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा।

23 जनवरी 2025 को मंत्रीपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन की ओर से सौरव शर्मा संपादक द्वारा हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित व प्रकाशित तथा कार्यालय बेज नं. 49–52, प्रथम तल, सेक्टर–2, पंचकूला ।
दूरभाष : 0172–2560340, 2560332 हरकोप्रैस : 0172–2637264